

भारत और क्षेत्रीय शक्तियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगान सत्ता अपने लोगों के अधिकारों का सम्मान करें।

मॉस्को में तालिबान अधिकारियों के साथ 10 देशों की बैठक में भारत की भागीदारी और एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करना जो अफगानिस्तान में "नई वास्तविकता" को मान्यता देता है, इस्लामी समूह के प्रति देश के दृष्टिकोण में एक निर्णायक बदलाव का संकेत देता है। भारत ने पहले तालिबान के साथ किसी भी तरह के जुड़ाव के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था।

हाल के महीनों में, जब तालिबान काबुल की ओर लगातार आगे बढ़ रहा था, तब भारत ने दोहा (कतर की राजधानी) में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के साथ संपर्क स्थापित किया था। लेकिन यह पहली बार है जब भारत ने तालिबान के एक शीर्ष प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जिसमें उप प्रधान मंत्री अब्दुल सलाम हनफी शामिल थे।

अफगानिस्तान में भारत के महत्वपूर्ण हित हैं। 20 वर्षों में, भारत ने अरबों डॉलर का निवेश किया है जिसे वह सुरक्षित करना चाहता है। पिछली बार तालिबान, जिनके **लश्कर और जैश** जैसे भारत विरोधी आतंकवादी समूहों के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, सत्ता में थे, भारत ने कश्मीर में हिंसक घटनाओं में वृद्धि के साथ-साथ कंधार में एक भारतीय विमान के अपहरण को देखा। अब तालिबान का कहना है कि वे किसी भी आतंकी संगठन को अफगान की धरती का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। यह सुनिश्चित करना भारत के हित में है कि तालिबान वार्ता पर चले। वह एक अलग तालिबान को पाकिस्तानी उपग्रह होते हुए नहीं देखना चाहेगा। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, अफगानिस्तान में नई वास्तविकता को देखते हुए, तालिबान के साथ जुड़ाव एक रणनीतिक आवश्यकता है।

लेकिन यह एक ऐसी नीति है जिसे द्विपक्षीय संबंधों की तुलना में क्षेत्रीय कूटनीति के माध्यम से अधिक आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। द्विपक्षीय रूप से, तालिबान के ऊपर भारत का ज्यादा दबदबा नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान की नई सत्ता, जो पतन की कगार पर खड़ी अर्थव्यवस्था से जूझ रही है इस बार क्षेत्रीय शक्तियों के साथ जुड़ने के लिए अधिक उत्सुक हैं। ऐसे में **मास्को-10** बैठक, जिसमें चीन, पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशियाई गणराज्य शामिल हैं, का कुछ लाभ है। तालिबान को अपने आतंकी संबंधों को तोड़ते हुए और अफगानिस्तान को स्थिर होते हुए देखने में भी इन देशों के साझा हित हैं।

यदि नहीं, तो अस्थिरता एक बार फिर अफगानिस्तान की सीमा के बाहर फैल सकती है। इसके लिए तालिबान को अपनी सरकार को खोलने, अन्य राजनीतिक और जातीय समुदायों के साथ सत्ता साझा करने और अफगानों के मौलिक अधिकारों का सम्मान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अफगानिस्तान के इतिहास के पिछले 40 साल इस बात के क्रूर उदाहरण हैं कि अगर एक पार्टी या समूह सभी शक्तियों को अपने हाथों में लेने की कोशिश करता है तो क्या गलत हो सकता है।

इन ऐतिहासिक उदाहरणों के बावजूद, तालिबान ने अपने तरीके बदलने के लिए बहुत कम तत्परता दिखाई है। संयुक्त बयान में, भारत और अन्य क्षेत्रीय देशों ने तालिबान से एक समावेशी सरकार बनाने पर अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि उनके क्षेत्र का उपयोग आतंकवादी समूहों द्वारा नहीं किया जा रहा है। ये प्रयास मात्र बयानों तक ही समाप्त नहीं होने चाहिए।

जबकि भारत और अन्य क्षेत्रीय देशों को आर्थिक संकट की इस अवधि के दौरान अफगानों की मदद करनी चाहिए। उन्हें अपने सामूहिक आर्थिक और राजनीतिक दबदबे का उपयोग तालिबान पर वहाँ के घरों पर राजनीतिक रियायतें देने के लिए दबाव बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए।

GS
World

Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. अभी हाल ही में तालिबान प्रतिनिधियों से दस देशों की बैठक किस स्थान पर आयोजित हुई है?

- (a) मास्को
- (b) दिल्ली
- (c) काबुल
- (d) दोहा

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. In which place was the meeting of ten countries with Taliban representatives held recently?

- (a) Moscow
- (b) Delhi
- (c) Kabul
- (d) Doha

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. 'पाकिस्तान-चीन के बढ़ते हस्तक्षेप के मद्देनजर भारत को तालिबान से वार्ता करना आवश्यक है।' इस कथन का विश्लेषण कीजिए साथ ही हालिया 'मास्को-10' वार्ता के महत्व को भी रेखांकित कीजिये।

(250 शब्द)

Q. 'In view of the increasing interference of Pakistan-China, India is required to hold talks with the Taliban.' Analyze this statement and also underline the importance of the recent Moscow-10 talks.

(250 Words)

Committed To Excellence

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।